छटा बिक्रस सम्मेलन फोर्टालेजा, ब्राजील

छटा ब्रिक्स सम्मेलन, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह के देशों की छटी वार्षिक कूटनीतिक बैठक है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसका आयोजन ब्राजील द्वारा किया गया, जो वर्तमान पांच-वर्षीय सम्मेलन चक्र का प्रथम मेजबान राष्ट्र है। मेजबान शहर फोर्टालेजा है, जहां जुलाई 14-16, 2014 के दौरान ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया।

ब्रिक्स सम्मेलन में सामाजिक समावेशन और स्थायी विकास पर बल दिया गया। बहस "समावेशी विकास : स्थायी समाधान" विषय के इर्द-गिर्द केन्द्रित रही। इस सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही ब्रिक्स के दूसरे चक्र का भी उद्घाटन हुआ। अभी तक प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इस समूह की एक बैठक की मेजबानी कर चुका है।

पृष्ठभूमि और सदस्य

2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले इस समूह को "ब्रिक" के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील देश हैं या नव-औद्योगिक राष्ट्र हैं, परन्तु वे अपनी व्यापक और तेजी से विकासमान अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण जाने जाते हैं; सभी पांचों सदस्य जी-20 समूह के भी सदस्य हैं।

इंडोनेशिया और टर्की का नाम ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता चाहने वाले देशों के रूप में लिया जा रहा है, जबकि अर्जेन्टिना, मिस्र, ईरान, नाइजीरिया और

सीरिया ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जतायी है। 2013 की स्थिति की अनुसार ब्रिक्स के पांच देश विश्व की 40 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका संयुक्त न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 16.039 अमरीकी डॉलर है। विश्व की अर्थव्यस्था में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है।

ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2001 में जाने माने अर्थशास्त्री जिम ओ' नील ने अपने प्रकाशन, *बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनोमिक्स ब्रिक्स* में किया था।

न्यू डिवेलॅप्मेंट बैंक (नया विकास बैंक) और कंटिन्जेन्ट रिजर्व अरेन्जमेंट (सीआरए) (आकस्मिक आरक्षित प्रबंध)

ब्रिक्स के नेताओं ने 100 अरब अमरीकी डालर के विकास बैंक और एक करेंसी रिजर्व पूल की स्थापना की। बैंक का लक्ष्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना है। पांच देशों के समूह के नेताओं ने सम्मेलन में घोषणा की कि इसका मुख्यालय शंघाई में होगा और भारत प्रथम पांच वर्षों तक बैंक की अध्यक्षता करेगा, उसके बाद ब्राजील और फिर रूस इसकी अध्यक्षता करेगा।

नए विकास बैंक संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर के समय ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की बैठक हुई और उन्होंने बैंक की भावी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय किए :-

क) बैंक के अध्यक्ष का पद बारी-बारी से संभाला जायेगा और इसका क्रम इस प्रकार होगा : भारत/ब्राजील/रूस/दक्षिण अफ्रीका/चीन।

ख) मुख्यालयों के साथ-साथ जोहानेस्बर्ग में प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना भी की जायेगी।

ग) बाद में आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यालय ब्राजील, भारत और रूस में खोले जायेंगे। दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय ब्राजील में खोला जायेगा।

घ) बैंक में यथाशीघ्र एक विशेष निधि सृजित की जायेगी, जिसमें सभी संस्थापक सदस्यों की भागीदारी होगी, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं की तैयारी और उनके कार्यान्वयन में मदद करना होगा। इसमें सबसे ज्यादा योगदान चीन करेगा।

ड.) बैंक के स्टॉफ की नियुक्तियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप योग्यता के सिद्धांत के आधार पर की जायेंगी।

ब्रिक्स नेताओं ने 100 अरब अमरीकी डॉलर का करेंसी रिजर्व पूल भी स्थापित किया ताकि पहले से रूकी हुई परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि नक़दी दबाव दूर करने में सदस्य देशों की सहायता की जा सके।

आकस्मिक करेंसी पूल को प्रत्येक ब्रिक्स राष्ट्र में सुरक्षित निधि के रूप में कायम किया जायेगा और भुगतान संतुलन की कठिनाइयां दूर करने में मदद देने के लिए अन्य सदस्य राष्ट्र में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

दुनिया में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला चीन आकस्मिक करेंसी पूल में सबसे अधिक या 41 अरब डॉलर का योगदान करेगा। ब्राजील, भारत और रूस 18-18 अरब डॉलर का योगदान करेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी 5 अरब डॉलर की होगी। आवश्यकता पड़ने पर चीन अपना अंशदान आधा करने की मांग करने का पात्र होगा, दक्षिण अफ्रीका दुगुना कर सकेगा और शेष राष्ट्र बकाया राशि का योगदान कर सकेंगे।

फोर्टलेजा कार्य योजना

भविष्य में अमल करने के लिए सदस्य देशों ने सम्मेलन में एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया, जिसकी महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं : -

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के साथ ब्रिक्स विदेश मंत्रियों/अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्रियों, ब्रिक्स शेरपाओं और सॉस-शेरपाओं की बैठक, जी-20 बैठकों, विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश बैठकों के साथ ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठकें, साथ ही आवश्यकता अनुसार स्वतंत्र रूप से बैठकें।

2. बहुराष्ट्रीय कार्यक्रमों के अवसर पर अथवा अलग से ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठकें, ब्रिक्स कृषि सहयोग कार्यकारी समूह की बैठक से पहले ब्रिक्स के कृषि और कृषि विकास मंत्रियों की बैठकें, ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स के शिक्षा मंत्रियों की बैठक।

3. आवश्यकता अनुसार ब्रिक्स स्थाई मिशनों और/या दूतावासों के बीच परामर्श, बैठकों का आयोजन न्यूयार्क, विएना, रोम, पेरिस, वाशिंग्टन, नैरोबी और जिनेवा में जहां भी उचित समझी जाए।

4. स्थाई विकास, पर्यावरण और जलवायु संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जहां भी उचित हो, सम्बद्ध बैठकों के साथ ब्रिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों की परामर्श बैठक।

5. खेल और बड़ी खेल प्रतियोगिताएं।

तलाश किए जाने वाले सहयोग के नए क्षेत्र

बैठक में सहयोग के नए क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया :-

- उच्चतर शिक्षा, डिग्रियों और डिप्लोमों को परस्पर मान्यता देना;
- श्रम और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशन संबंधी सार्वजनिक नीतियां;
- विदेशी नीति आयोजना संवाद;
- बीमा और पुनर्बीमा;
- ई-कॉमर्स के बारे में विशेषज्ञों के सेमिनार;

15 जुलाई को समूह ने 100 अरब अमरीकी डॉलर के ब्रिक्स विकास बैंक और एक कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट (सीआरए) की स्थापना के बारे में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। सीआरए 100 अरब अमरीकी डॉलर का एक रिजर्व करेंसी पूल होगा जो भुगतान संतुलन की कठिनाइयों की स्थिति में ब्रिक्स देशों के लिए एक सुरक्षा के रूप में उपलब्ध होगा। ब्रिक्स निर्यात

क्रेडिट एजेंसियों के बीच सहयोग संबंधी दस्तावेज और नवाचार के बारे में सहयोग के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के व्यापार से संबंधित मंत्रियों की बैठक 14 जुलाई, 2014 को छठे ब्रिक्स सम्मेलन की पूर्व संध्या पर फोर्टलेजा, ब्राजील में हुई।

वैश्विक आर्थिक गतिविधियां और व्यापार एवं निवेश पर उनका प्रभाव

1. ब्रिक्स के व्यापार मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा की और मंदी से बहाली की धीमी गति पर चिंता प्रकट की, जो व्यापार और निवेश के प्रवाह में निरंतर बाधा बनी हुई है। उन्होंने यह महसूस किया कि विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि और नीतिगत कार्रवाइयों के बारे में अनिश्चितता के चलते वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उसका और दुष्प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बेहतर नीति समन्वय और वैश्विक आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासन संरचनाओं को अद्यतन बनाना एक अनिवार्यता है।

2. मंत्रियों ने विश्वास व्यक्त किया कि चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण के बावजूद, ब्रिक्स देश वैश्विक आर्थिक बहाली में योगदान करना जारी रखेंगे। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश के विस्तार का स्वागत किया और संकल्प व्यक्त किया कि वे अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने

अपना यह संकल्प दोहराया कि वे विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों के प्रतिकूल व्यापार संरक्षणतावादी उपायों से परहेज करेंगे, जबकि विकासशील देशों के प्रति विशेष और विभेदक बर्ताव का सम्मान करेंगे।

विश्व व्यापार संगठन में भूमिका की वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता

3. ब्रिक्स के व्यापार मंत्रियों ने दिसंबर 2013 में बाली में हुए विश्व व्यापार संगठन कें मंत्री-स्तरीय सम्मेलन की सफलता पर विचार किया। उन्होंने बाली मंत्री-स्तरीय निर्णयों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तत्संबंधी समय-सीमा के भीतर हासिल करने के लिए जोरदार ढंग से काम करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने एक मुक्त और नियम आधारित बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के महत्व को स्वीकार किया और वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित करने में डब्ल्यूटीओ की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया।

4. मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि विकास के लक्ष्य के आधार पर दोहा दौर की बातचीत के निष्कर्ष विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ पूरी तरह एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से जुड़े हुए हैं।

5. मंत्रियों ने अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि वे यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में समन्वय करेंगे कि डब्ल्यूटीओ में तय किया जाने वाला कार्यक्रम सभी स्तंभों के लिए संतुलित, पारदर्शी, समावेशी और

विकासोन्मुखी परिणाम लाने वाला हो। मंत्रियों ने इस बात की भी पुष्टि की कि कार्यक्रम के मध्य में कृषि और विकास के आयाम को रखा जाना चाहिए और उन मुद्दों को वरीयता दी जानी चाहिए, जिनके बारे में बाली मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में कानूनी रूप में बाध्यकारी परिणाम हासिल नहीं किए जा सके। मंत्रियों ने एनएएमए और सेवाओं के महत्व को भी स्वीकार किया और इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि वर्तमान दोहा समझौतों की दिशा में काम किया जाए।

व्यापार और निवेश मामलों में ब्रिक्स सहयोग

6. मंत्रियों ने यह महसूस किया कि व्यापार और निवेश का रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान है और वे सुदृढ़, स्थाई और संतुलित वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी जरूरी हैं।

7. मंत्रियों ने आर्थिक और व्यापार मुद्दों के लिए संपर्क समूह (सीजीईटीआई) द्वारा तैयार किए गए संयुक्त व्यापार अध्ययन का भी स्वागत किया। इस अध्ययन में सदस्य देशों के बीच मूल्य संवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने और अंतरा-ब्रिक्स व्यापार का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। उन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन किया और सीजीईटीआई को निर्देश दिया कि वह अपनी सिफारिशों पर निरंतर कार्य करे।

8. मंत्रियों ने आर्थिक सहयोग मजबूत करने और ब्रिक्स के बीच व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों के संबंध में सीजीईटीआई में हुए विचार विमर्श पर ध्यान दिया।

9. मंत्रियों ने सीजीईटीआई द्वारा विकसित ब्रिक्स व्यापार एवं निवेश सुविधा कार्य योजना को मंजूरी दी। उन्होंने महसूस किया कि यह योजना ब्रिक्स व्यापार और निवेश सहयोग फ्रेमवर्क पर आधारित है और ब्रिक्स सदस्यों को प्रोत्साहित किया कि वे इसे स्वेच्छा से लागू करें।

10. मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों के बारे में निरंतर वार्ता के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने निवेश संधियों के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वयंसेवी संदर्भ के रूप में तैयार किए गए दस्तावेज "अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों के बारे में ब्रिक्स संदर्श" में रेखांकित सिद्धांतों का अध्ययन किया।

11. मंत्रियों ने ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अंतरा-ब्रिक्स सहयोग सुदृढ़ करने के महत्व पर बल दिया, ताकि अंतरा-ब्रिक्स व्यापार के लिए अवसरों का विस्तार किया जा सके और घनिष्ठ आर्थिक सहयोग में वृद्धि की जा सके। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में ब्रिक्स विशेषज्ञ संवाद कायम करने के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने सीजीईटीआई को निर्देश दिया कि वह निर्यात संवाद के लिए व्यापक कार्य शर्तें स्पष्ट करे।

12. मंत्रियों ने "ब्रिक्स आर्थिक सहयोग कार्यनीति" और "ब्रिक्स घनिष्ठ आर्थिक भागीदारी फ्रेमवर्क" दस्तावेज का अनुमोदन किया और ब्रिक्स के

बीच आर्थिक सहयोग, विशेषकर व्यापार एवं निवेश में सहयोग के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए दिशा निर्देश तय करने के प्रयासों का स्वागत किया।

13. मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों के सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के बीच घनिष्ठ संपर्क कायम करने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार करें। इसके अंतर्गत एमएसएमई नियामक फ्रेमवर्क संबंधी जानकारी का आदान प्रदान, व्यापार से व्यापार सम्पर्कों को प्रोत्साहन और एमएसएमई सहयोग के लिए समुचित संस्थागत फ्रेमवर्क की पहचान के क्षेत्र में सहयोग शामिल है।

ब्रिक्स देशों के बीच संवाद के मुख्य क्षेत्र और विषय

सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की बैठकों से परे ब्रिक्स देशों के बीच कई मंचों पर विचार विमर्श हुआ। इसमें मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, व्यापारी और शिक्षाविदों की बातचीत शामिल थी।

वित्त एवं केंद्रीय बैंक

ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक पहली बार नवंबर, 2008 में साओपाउलो में हुई थी। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संगठन पर विचार करने के

लिए इस बैठक का सुझाव ब्राजील द्वारा येकातेरिनबर्ग में विदेश मंत्रियों की एक बैठक में दिया गया था।

साओपाउलो की बैठक से एक महीना पहले लेहमन ब्रदर्स के दिवालिया होने से संकट उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप जी-20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक बुलाई गई। इस संदर्भ में ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्यसूची के बारे में अपना सहयोग और गहन बनाएंगे।

उसके बाद से जी-20 सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की लगातार बैठकें हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की द्विवार्षिक बैठकों, ब्रिक्स सम्मेलनों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के अवसर पर भी ब्रिक्स के विदेश मंत्री मिलते हैं।

व्यापार

ब्रिक्स के व्यापार मंत्रियों की परंपरागत बैठक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर आयोजित की जाती है। वे डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठकों के अवसर पर भी अलग से बैठक करते हैं।

आर्थिक और व्यापार मुद्दों से संबंधित संपर्क समूह (सीजीईटीआई), जो व्यापार मंत्रियों को रिपोर्ट करता है, संस्थागत फ्रेमवर्क प्रस्तावित करने, और ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापार संबंधी मुद्दों के बारे में सहयोग के विस्तार के लिए ठोस उपाय करने के प्रति जवाबदेह है।

व्यापार मंच और परिषद

ब्राजील की पहल पर 2010 से ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक सम्मेलनों की पूर्व संध्या पर आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य नए व्यापार अवसरों की पहचान सहित व्यापार और आपसी निवेश का विस्तार करना और उसमें विविधता लाना है। ब्राजील की यह मंशा रही है कि इस मंच के अंतर्गत लघु और मझौले उद्यमों और पर्यटन के क्षेत्रों को शामिल किया जाए।

2013 में ब्रिक्स व्यापार परिषद की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश तथा व्यापार वातावरण संबंधी अन्य मुद्दों के बारे में सिफारिशें देना था। परिषद में प्रत्येक देश की कंपनियों के पांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। ब्राजील के प्रतिनिधियों में वाले, वेग, बानको दोब्रासिल और मार्कोपोलो (ब्राजीलियाई शाखा के अध्यक्ष) शामिल हैं। परिषद के सदस्य अपनी सिफारिशें ब्रिक्स सम्मेलन के नेताओं को प्रस्तुत करेंगे।

वित्तीय मंच

ब्रिक्स के राष्ट्रीय विकास बैंकों के बीच सहयोग 2010 में दूसरे सम्मेलन (ब्रासिलिया, 2010) में प्रारंभ हुआ। उसके बाद से नेशनल बैंक फार इकोनोमिक एंड सोशल डिवेलपमेंट (बी एंड डीईएस), व्नेशेकोनोम बैंक, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, चाइना डिवेलपमेंट बैंक कारपोरेशन और

दक्षिण अफ्रीकी डिवेलपमेंट बैंक के अध्यक्षों की बैठक ब्रिक्स सम्मेलन के समानांतर होती है। ऐसी बैठकों को ब्रिक्स फाइनेंशियल फोरम यानी वित्तीय मंच की बैठक कहा जाता है। अभी तक ब्रिक्स के विकास बैंकों द्वारा वित्तीय सहयोग के बारे में आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

शैक्षिक मंच और विचारकों की परिषद (अकेडमिक फोरम एंड थिंक टैंक काउंसिल)

2010 से ब्रिक्स के शैक्षिक मंच की बैठक सम्मेलनों से पहले हर वर्ष आयोजित की जाती है। इन बैठकों में बड़ी संख्या में पांच देशों के विशिष्ट प्रोफेसर हिस्सा लेते हैं। ब्रिक्स की प्रक्रिया में सिविल सोसायटी की भागीदारी का यह एक महत्वपूर्ण मंच है। इन बैठकों में सदस्य देशों को अपने समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों के बारे में मौलिक विचार-विमर्श की सुविधा प्राप्त होती है।

ब्रिक्स विचारक परिषद की स्थापना 2013 में हुई। इसमें निम्नांकित संस्थान शामिल हैं :- इंस्टिट्यूट आफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (ब्राजील); नेशनल कमेटी फॉर ब्रिक्स रिसर्च (रूस); ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (इंडिया); चाइना सेंटर फार कंटम्परेरी वर्ल्ड स्टडीज़ (चीन) और ह्यूमन साइंस रिसर्च काउंसिल (दक्षिण अफ्रीका)। परिषद सूचना के आदान प्रदान और समप्रेषण; अनुसंधान, नीति विश्लेषण और संदर्श

अध्ययन; और क्षमता निर्माण के प्रति जिम्मेदार है। मंच और परिषद की सिफारिशें नेताओं को संबोधित की जाती हैं। शैक्षिक मंच और विचारक परिषद दोनों की बैठक मार्च, 2014 में रिओ-डि-जेनेरो में आयोजित की गई थी।

स्वास्थ्य

ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2011 से नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की बैठकों के अवसरों पर भी इन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होती है। डब्ल्यूएचओ कार्यसूची से संबंधित मुद्दों पर समन्वय करने के अलावा यह समूह एक प्रौद्योगिकी विषयक सहयोग नेटवर्क कायम करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इस पहल के लक्ष्यों में से एक उन प्रौद्योगिकियों के अंतरण और उन तक पहुंच को प्रोत्साहित करना है, जिनसे विकासशील देशों में दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और उनके मूल्यों में कमी लाई जा सके। तीन मंत्री स्तरीय वक्तव्यों (पेइचिंग, नई दिल्ली और केपटाउन) में यह नेटवर्क कायम करने की इच्छा व्यक्त की गई। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं में सहयोग के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क की स्थापना को 2013 में मंजूरी दी गई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

2011 से वरिष्ठ अधिकारियों की कई वार्षिक बैठकों के बाद ब्रिक्स के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की पहली बैठक फरवरी 2014 में क्लेइनमोंड में हुई। ब्राजील की अस्थाई अध्यक्षता में होने वाली अगली मंत्री स्तरीय बैठक में इस क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सहयोग के लिए एक कार्यनीतिक फ्रेमवर्क कायम करना है। समझौता ज्ञापन से ब्रिक्स के अनुभवों और जानकारी के आधार पर विकासशील देशों में अन्य सम्बद्ध पक्षों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। अंटार्कटिक महाद्वीप सहित समुद्र विज्ञान और ध्रुवीय अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग की विशेष संभावनाएं हैं।

सुरक्षा

सुरक्षा से संबंधित ब्रिक्स के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों की बैठकें 2009 से आयोजित की जा रही हैं। अद्यतन बैठक (केपटाउन, दिसंबर 2013) में साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, यातायात सुरक्षा और क्षेत्रीय संकटों के बारे में विचारों का आदान प्रदान हुआ। साइबर सुरक्षा के बारे में एक कार्य दल का गठन किया गया है; अन्य लक्ष्यों के अलावा, यह दल अंतर्राष्ट्रीय जगत में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा और इस दिशा में ब्रिक्स का दृष्टिकोण तय करने के लिए समन्वय करेगा।

ब्रिक्स के कृषि और कृषि विकास मंत्रियों की बैठक पहली बार 2010 में मास्को में हुई। उसके अगले वर्ष चेंग्दू में हुई बैठक में 2012-2016 के लिए एक कार्य योजना मंजूर की गई। इसमें कृषि के क्षेत्र में पांच देशों के बीच सहयोग के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए। कृषि विशेषज्ञों के एक कार्यदल का भी गठन किया गया जिसे मंत्री स्तरीय बैठकों से पहले तैयारी विषयक बैठकों का कार्य सौंपा गया।

आंकड़े

2010 से ब्रिक्स का संयुक्त सांख्किीय प्रकाशन हर वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर किया जाता है। सदस्य देशों के विशेषज्ञ नियमित रूप से मिलते हैं ताकि इस दस्तावेज को तैयार किया जा सके। अद्यतन प्रकाशन डरबन शिखर सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन का 2014 का संस्करण ब्राजीलियन इंस्टिट्यूट आफ ज्योग्राफी एंड स्टेटिस्टिक्स (आईपीजीई) द्वारा तैयार किया जाएगा और छठे सम्मेलन के दौरान इसे प्रकाशित किया जाएगा।

(स्रोत : छठा ब्रिक्स सम्मेलन) http://www.brics6.itamaraty.gov.br/